(c) As reported in the 13th Brochure, the number of Central Government Civilian employees (regular) was 37.48 lakhs as on 31st March, 1989 and the expenditure on Pay and Allowances of Central Government Civilian employees (regular) was Rs. 9687.99 crores in 1990-91.

(d) Instructions have been issued to all Ministries|Departments to reduce their staff strength by at least 10 per cent. Orders have also been issued that the posts remaining unfilled for more than one year should be abolished.

Adjustment of SEBs Dues

2637. DR. SHRIKANT RAMACHANDRA JICHKAR: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what are the names of the State Electricity Boards whose dues to the CPSU are being adjusted from their Central assistance to States;

(b) whether the Finance Commission had given a specific authority to do such a thing;

(c) if not, under what authority this is being done; and

(d) whether the States have protested this move, if so, what are the names of the States which have protested this?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) Overdues of all the 25 State Electricity Boards (SEBs)/State Governments to the Central Public Sector Undertakings (CPSUs) are being adjusted from the Central plan assistance of the States.

(b) No, Sir.

(c) The adjustment is being made in persuance to the decisions taken by the Central Government on 8.6.1990 and 10.8.1992 regarding adjustment of SEBs dues to CPSUs against Central Plan assistance of the States.

(d) Yes, Sir. Some of the State Governments namely Andhra Pradesh, Bihar, Haryana, Maharashtra, Madhya Pradesh, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu and Uttar Pradesh have represented against the adjustment of SEBs dues to CPSUs against Central plan assistance of the States.

RBI guidelines for relief in areas *affected by Natural Calamities*

2638. SHRI V. RAJESHWAR RAO: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Reserve Bank of India propose to review the general guidelines for relief measures to be followed by banks in areas affected by natural calamities issued by RBI on 2nd August, 1984;

(b) if so, what are the review measures contemplated;

(c) if not, what are the reasons for not reviewing the guideines; and

(d) what are the exact guidelines which presently exist?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FNANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MININSTRY OF PARLIAMENTARY RFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) to (d) The review of standing guidelines for relief measures to be followed by banks in areas affected by natural calamities is a continuous process. Amendments to the guidelines are made whenever the situation so warrants. Suggestions received in this regard are examined and amendments made, where considered necessary. The guidelines for relief to persons affected by natural calamities, are applicable in the event of a drought, flood,, cyclone, tidal waves and other natural calamities. On

the declaration of Annewari or pending its declaration where the District Collector certifies that the crop yield is below 50 per cent of the normal yield and District Consultative Committee (DCC) is satisfied about it, quick relief measures have to be initiated by banks as per the guidelines. The beneficiaries are farmers rural artisans, traders and self-employed owners of small and tiny units. The standing guidelines *inter-alia* envisage (i) conversion of short term production loans into medium terms loans (ii) rescheduling postponment of existing term loan in stalments, (iii) provision of additional need based crop loans/working capital and (iv) relaxation in security and margin norms etc.

मोदी सीमेंट लिमिटेड द्वारा शेयरों की खरीद-बिक्री

2639. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मोदी सीमेंट लिमिटेड शेयरों की खरीद-बिक्री विहित कानूनों और नियमों के अनुसार करता रहा है और क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है; यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं;

(ख) क्या वित्त मंत्री को मोदी सीमेंट लिमिटेड द्वारा शेयरों की खरीद में अनियमितता बरतने तथा गोलमाल करने और मैसर्स निशा एंड कम्पनी, मोहम्मदाबाद, गोहना जिला, मऊ, उत्तर प्रदेश के शेयर धन को हड़प लेने के बारे में संसद के कुछ माननीय सदस्यों एवं भारत सरकार में राज्य मंत्री श्री कल्पनाथ राय तथा अन्य प्रमुख व्यक्तियों के पत्र मिले हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई हैं और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा अबरार अहमद) : (क) कम्पनी कार्य विभाग ने सूचित किया है कि उसे मैसर्स मोदी सीमेंट लि० से पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 372 के अन्तर्गत अन्य कम्पनियों से शेयर खरीदने के लिये अनुमति मांगने संबंधी कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार से पूर्व अनुमोदन केवल उन मामलों में अपेक्षित होता है जब कम्पनी का निवेश दूसरे निगमित निकायों में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 372 के अर्न्तगत निर्धारित सीमा से बढ़ जाता है, कम्पनी कार्य विभाग के ध्यान में कम्पनी द्वारा किसी कानून का उल्लघंन करने की बात सामने नहीं आई है।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार में राज्य मंत्री श्री कल्पनाथ राय और सांसद श्री ईशदत्त यादव ने मोदी सीमेंट लि० द्वारा मैसर्स खान ट्रेडर्स/निशा एण्ड कम्पनी, मोहम्मदाबाद गोहना, मऊ, उ० प्र० को शेयरों का आबंटन न करने के संबंध में वित्त मंत्री को पत्र भेजे थे। इस मामले को कम्पनी कार्य विभाग के साथ उठाय गया था। संबंधित विभाग के अनुसार, मैसर्स खान ट्रेडर्स को दि० 23-3-1986 को मोदी सीमेंट लि० के 2500 शेयर आबंटित किये गये थे और उससे (मै० खान ट्रेडर्स), यह अपेक्षा की गई थी कि वह शेष आबंटन राशि का प्रति शेयर 5/- रु0 के हिसाब से कुल 12500/- रु0 का भुगतान करें। परन्तु अनस्मारक पत्र भेजे जाने के बाद भी मै० खान ट्रेडर्स ने शेष राशि को जमा नहीं कराया है। इस लिये दि० 7-1-1990 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा कम्पनी ने अंतिम नोटिस जारी किया था जिसमें दि0 28-2-90 तक शेष राशि का भुगतान करने का अनरोध किया गया था। और ऐसा न करने पर बिना और नोटिस के शेयरों को जब्त कर लेने की बात कही गई थी। कि मै० खान ट्रेडर्स ने निश्चित तारीख तक शेष राशि का भुगतान नहीं किया है, इसलिये कम्पनी के निदेशक बोर्ड ने अपने संस्था के अन्तर्नियम के अनुसार शेयरों का जब्ती का निर्णय